

(३) .
व्यायालय राजस्व मण्डल, म ० प्र ० ग्वालियर

समक्ष

डॉ० मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक २५६।-तीन/२०१५ विरुद्ध आदेश दिनांक
३०.७.२०१५ - पारित द्वारा तहसीलदार, करैरा जिला शिवपुरी -
प्रकरण क्रमांक ३४ अ ७०/२०१४-१५

परमाल सिंह पुत्र प्रेमी जाटव
फिल्टर रोड करैरा जिला शिवपुरी

—आवेदक

विरुद्ध

पवन पुत्र जगदीश यादव
ग्राम काली पहाड़ी कृषक कस्बा करैरा

—अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री सुश्री एस०पी०धाकड़)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री पी०के०तिवारी)

अ । दे श

(आज दिनांक १० नवम्बर, २०१५ को पारित)

तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक ३४
अ ७०/ २०१४-१५में पारित आदेश दिनांक ३०.०७.२०१५ के
विरुद्ध यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के
अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारोंश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार करैरा को
मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा २५० के अंतर्गत
आवेदन देकर बताया कि उसके नाम कस्बा करैरा में कुल किता ०८
कुल रकबा ०.६७० हैक्टर भूमि है। सर्वे क्रमांक २३५७ के रकबा
०.०५० है। पर आवेदक ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है इसलिये
उसका कब्जा हटवाया जाकर कब्जा दिलाया जावे। तहसीलदार करैरा ने

al

26

प्रकरण क्रमांक 34 अ 70/ 2014-15 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.07.2015 पारित करके आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि पर किये गये कब्जे को एक सप्ताह में हटाकर सौंपे जाने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

३/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

४/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार करैरा के प्रकरण क्रमांक 34 अ 70/ 2014-15 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ने उसके नाम की भूमि सर्वे क्रमांक 2357 के रकबा 0.050 है। पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा करना बताते हुये कब्जा वापिस दिलाने की मांग की है एंव दूसरा आवेदन देकर बताया कि उसके स्वत्व की भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया है जिसे रोका जावे। मौके की तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखकर तहसीलदार करैरा ने अंतरिम आदेश दिनांक 16-4-15 से निर्माण कार्य पर रोक भी लगाई है, जिसकी प्रतिलिपि आवेदक को भी पृष्ठांकित की है एंव सुनवाई हेतु पेशी 7-4-15 नियत कर नोटिस भी जारी किया है। आवेदक तहसीलदार के समक्ष सुनवाई हेतु अभिभाषक श्री प्रदीपकुमार जोशी के साथ 7-4-15 को उपस्थित हुआ है एंव बचाव में संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर आपत्ति दर्ज कराई है तथा आगामी तिथि 24-4-15 को बचाव में अनावेदक के दावे का उत्तर प्रस्तुत किया है। तहसीलदार ने मौके की जांच राजस्व निरीक्षक से कराई, जिसमें अनावेदक की वादोक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा होना पाया गया है, तदुपरांत आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अंतरिम

८

आदेश दिनांक 30.07.2015 से आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि पर किये गये कब्जे को एक सप्ताह में हटाकर सौंपे जाने के आदेश दिये हैं, जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 34 अ 70/ 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(डॉ मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मोप्रग्वालियर